extent of protection afforded to by it to depositors as at the end of 1985, 1986 and 1987 are furnished in the following table:

(Amount in crores of Rs.)

	1985	1986	1987
1. Assessable Deposits	76,517	86,214	103,044
2. Insured Deposits	56,211	62,878	75,511
3. Percentage of 2 to 1	73.05	72.9	73.3
4. Total number of accounts (in lakhs)	2,238	2,360	2,569
5. Fully protected accounts (in lakhs)	2,145	2,320	2,518
6. Percentage of 5 to 4	95.8	98.0	98.0

Further the year-wise amount of guaranteed advonces in respect of farmers and agriculturists for the last three years 1985, 1986 and 1987 (latest available), under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 of DICGC was Rs. 5057.75 crores, Rs. 6020.34 crores and Rs. 6428.29 crores respectively.

Cash credit to farmers

3509. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a request was made to the Central Government to provide cash credit facility to farmers in Maharashtra; and

(b) if so, what are the details thereof and Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) has reported that no such request was received by them. However, the public sector banks were advised by Government in April, 1988 to consider launching of credit card scheme on the lines of a scheme introduced by Dena Bank. The Scheme will facilitate the farmers with good track record to get the credit instantly and also dispense with execution of documents in each agricultural season. The Reserve Bank of India, in this regard, has reported that the Agricultural Credit Card Scheme has been introduced by Syndicate Bank, Canara Bank, Punjab National Bank, Andhra Bank, Bank of Maharashtra and Allahabad Bank, besides Dena Bank, on an experimental basis.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

3510. डा० अबरार अहमद खान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या है जिनमें गैर-सरकारी निदेशकों के पद आज की तारीख में रिक्त पड़े हैं ;

(ख) वर्तमान गैर-सरकारी निदेशकों को इन बैंकों में कब नियुक्त किया गया था और उनकी कार्यविधि कब समाप्त होनी थी ;

(ग) इस प्रकार के गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के क्या मानदंड हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्ति, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है । इस समय, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी बैंक के निदेशक-मण्डल में कोई गैर-सरकारी निदेशक नहीं है । अधिकांश, पद, जनवरी, 1985 से खाली है ।

स्वरोजगार कार्यक्रम

3511. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार कार्यक्रम के अधीन कितनी राशि रखी गई थी और इसके अधीन सहायता लेने के लिये बैंकों ने अभी तक कितने आवेदनपत्र प्राप्त किये और साथ ही इस कार्यक्रम के अधीन कितने लोग लाभान्वित हुये ;

(ख) राजस्थान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस कार्यक्रम के अधीन अभी तक सहायता प्राप्त की है और उनमें से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है ; और

(ग) देश में अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने इस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार योजना वर्ष 1986-87 के दौरान लागू की गई थी तथा इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई । अलबत्ता, 1981 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक शहरी केन्द्र में प्रत्येक 300 की आबादी पर एक हिताधिकारी को ऋण सहायता दी जानी है । वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के वास्तविक लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा सारे देश के लिये तथा राजस्थान में मंजूर किये गये ऋण नीचे दिये गये हैं :—

(संख्या लाखों में)

वित्तीय वर्ष	वास्तविक लक्ष्य (अनुमानित)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	मंजूर किये ऋणों की संख्या
अखिल भारतीय			
1986-87	5.00	5.36	3.41
1987-88	5.00	6,97	3.02
राजस्थान			
1986-87	0.23	0.30	0.20
1987-88	0.23	0.54	0.21

वर्ष 1988-89 की स्थिति वित्तीय वर्ष के अन्त तक ही ज्ञात हो सकेगी ।

बैंकों को वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों की अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है ।